

# Yogoda Satsanga Mahavidyalaya

B. Com Semester – VI (C-13) CBCS

**Subject: Auditing & Corporate Governance**

Topic: लिमिटेड कंपनी का ऑडिट

*Ravindra Kumar, Associate Professor Department of Commerce*

---

## लिमिटेड कंपनी का ऑडिट:

एक कॉर्पोरेट ऑडिट या लिमिटेड कंपनी के ऑडिट में उनकी सटीकता की पुष्टि करने के लिए उसके खाते की पुस्तकों की जांच करना शामिल है। संगठन को ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर का चयन करना होगा। किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के ऑडिट का उद्देश्य ऑडिटर को अपनी राय बताने में सक्षम बनाना है।

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') कई आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जिन्हें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पंजीकरण के समय पूरा करना होगा। कंपनी के आकार या प्रकृति के बावजूद, ऑडिटिंग अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है जिसका उसे पालन करना चाहिए। ऑडिटर को यह निर्धारित करने के लिए कई बहीखातों, वाउचरों और चालानों की जांच करनी चाहिए कि क्या वे सटीक और ठीक से प्रबंधित हैं। अधिनियम और कंपनी कानून विनियमों के लिए एक सीमित देयता निगम के वार्षिक ऑडिट की आवश्यकता होती है।

## एक लिमिटेड कंपनी के ऑडिट की आवश्यकता:

एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के तहत पंजीकृत होने के बाद कई आवश्यकताओं का पालन करना होगा। व्यवसाय के आकार या प्रकार की परवाह किए बिना, ऑडिट करना एक ऐसा दायित्व है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

कॉर्पोरेट ऑडिट उसके वित्तीय रिकॉर्ड की जांच है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सटीक हैं या नहीं। एक ऑडिटर को वह ऑडिट करना होगा जिसे फर्म नियुक्त करती है। किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के ऑडिट का लक्ष्य ऑडिटर को अपने निष्कर्ष निकालने का मौका प्रदान करना है।

ऑडिटर को यह देखने के लिए कई खातों की पुस्तकों, वाउचर और बिलों की जांच करनी चाहिए कि क्या वे सही हैं और अद्यतित हैं। अधिनियम और कंपनी कानून विनियमों के अनुसार, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अनुपालन के लिए वार्षिक ऑडिट करना होगा।

## ऑडिट के 3 मुख्य प्रकार:

एक प्राइवेट लिमिटेड व्यवसाय को विभिन्न कारणों से कई ऑडिट से गुजरना पड़ सकता है। निजी कंपनी ऑडिट निम्नलिखित रूप ले सकते हैं:

### 1.सांविधिक लेखा - परीक्षा

अपने लाभ या टर्नओवर के बावजूद, प्रत्येक प्राइवेट लिमिटेड व्यवसाय को वैधानिक ऑडिट से गुजरना आवश्यक है। जिस निगम को घाटा होता है, उसके लिए वैधानिक ऑडिट की भी आवश्यकता होती है। 2014 के अधिनियम और कंपनी (खाता) विनियम के अनुसार, प्रत्येक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने वार्षिक खातों का पूरी तरह से ऑडिट कराना होगा।

खातों की किताबों, बैंक बैलेंस और वित्तीय विवरणों में डेटा की समीक्षा करने के बाद, वैधानिक ऑडिट का लक्ष्य यह पता लगाना है कि क्या कोई फर्म अपनी वित्तीय स्थिति को सही ढंग से चित्रित कर रही है।

### 2.आंतरिक लेखा परीक्षा

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आंतरिक ऑडिट उसके आंतरिक प्रबंधन की सलाह पर किया जाता है। 2014 के अधिनियम और कंपनी (खाता) विनियमों के अनुसार, निर्दिष्ट फर्मों को अपने परिचालन का ऑडिट करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना होगा। नीचे सूचीबद्ध सीमित निजी निगमों को आंतरिक लेखापरीक्षा करना आवश्यक है:

1. पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम रु. के राजस्व वाले निजी व्यवसाय। 200 करोड़
2. निजी व्यवसाय जिन पर बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों का कम से कम रु. का बकाया ऋण है। 100 करोड़

3. संगठन की परिचालन प्रभावशीलता और उसके वित्त के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए आंतरिक ऑडिट किए जाते हैं। वे वित्तीय विश्लेषण करने और इसके संचालन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए आवश्यक समायोजन लागू करने में आंतरिक प्रबंधन की सहायता करते हैं।

### 3.लागत लेखापरीक्षा

निम्नलिखित प्राइवेट लिमिटेड फर्मों को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) विनियम, 2014 के तहत लागत ऑडिट करना आवश्यक है:

1. कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) विनियमों की तालिका 3 (ए) में दर्शाई गई वस्तुओं का उत्पादन करने वाली या सेवाएं प्रदान करने वाली निजी सीमित फर्म और निम्नलिखित विशेषताएं रखती हैं:

- इसकी सभी सेवाओं और उत्पादों से कुल वार्षिक राजस्व कम से कम रु. सबसे हालिया वित्तीय वर्ष के लिए 50 करोड़

- किसी सेवा या उत्पाद का कुल वार्षिक राजस्व कम से कम रु. 25 करोड़.

2. कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) विनियमों की तालिका 3 (बी) में दर्शाई गई वस्तुओं का उत्पादन करने वाली या सेवाएं प्रदान करने वाली प्राइवेट लिमिटेड फर्म और निम्नलिखित विशेषताएं रखती हैं:

- इसकी सभी सेवाओं या उत्पादों से वार्षिक राजस्व कम से कम रु. पिछले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़।

- कुल राजस्व कम से कम रु. विशिष्ट सेवा या उत्पाद के लिए 35 करोड़।

---

**Ravindra Kumar**  
**Associate Professor**  
**Department of Commerce**